MR. CHAIRMAN : See, I have to rotate. ...*(Interruptions)*...

Cotton production in Vidarbha

*445. SHRI AVINASH PANDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government has advised the farmers in Vidarbha region to desist from sowing of Bt. Cotton due to deficient rainfall in this season;

(b) if so, the expected decline in cotton production as a result of following this advisory;

(c) what alternatives have been suggested by Government; and

(d) whether these alternatives would cause a decline in the cotton farmers' income?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) In view of forecast for South West monsoon, the Central Institute for Cotton Research, Nagpur advised that dry seeding of varieties can be taken up during 16 to 20 June, 2014 for non Bt. cotton. For Bt. cotton, sowing should be done only after receipt of about 75-100 mm rainfall. After receipt of about 75-100 mm rainfall, intercropping of mung, urd, bean and short duration soyabean was recommended to avoid risk.

Vidarbha region of Maharashtra has received 411.7 mm rainfall against the normal of 515.7 mm during the period from 1.6.2014 to 3.8.2014. Delay in onset of monsoon initially resulted in slow area coverage under cotton in Vidarbha. However, area coverage subsequently improved with increased rainfall in the region. The area sown under cotton in Vidarbha region was 12.81 lakh hectares as on 28.7.2014 against the area of 12.30 lakh hectare sown up to the corresponding date last year. Sowing of cotton is still continuing. It is expected that production of cotton in Vidarbha region would be close to normal provided rains during remaining kharif season is normal and well distributed.

SHRI AVINASH PANDE: Sir, I would like to know from the hon. Minister how the farmers are expected to make up these losses. ...*(Interruptions)*... Sir, I would like to know from the hon. Minister as to how the farmers are expected to make up these losses in income. Is the Central Government planning to provide any financial assistance to make good for the decline in farmers' income and ensure that investment in agriculture for the next season is not adversely affected?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यह विदर्भ क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है और विदर्भ क्षेत्र में इस वर्ष जो इसकी बुआई हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा हुई है। मानसून प्रारंभ होने के समय थोड़े कम की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, उसकी तुलना में जो गत वर्ष 28 जुलाई तक 12.30 लाख हेक्टेयर जमीन में इसकी बुआई हुई थी, वह इस वर्ष 28 जुलाई तक 12.81 लाख हेक्टेयर जमीन में हो चुकी है। यह उसके बाद हुआ है, जब मानसून में सुधार हुआ है। यह जो 4 अगस्त की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 14 लाख 20 हेक्टेयर तक बुआई हो गई है। सवाल यहां उत्पादकता का है और हमारे यहां स्थिति यह है कि जो उसका घनत्व है, वह अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है और इस कारण उत्पादकता में असर पड़ता है। इसलिए इंटर-क्रॉप के लिए, अन्तर्फसलन के लिए राज्यों को सलाह दी गई है। अन्तर्फसलन करने से और खासकर जो इस समय दलहन की खेती की जाती है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा मिलती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। इस दृष्टि से हमारे वैज्ञानिक भी उन क्षेत्रों में पहुंचे हैं और इसके लिए हमने विदर्भ क्षेत्र के लिए अलग से राशि का एलोकेशन भी किया है।

श्री अविनाश पांडे : सर, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, उसके कारण कपास की उत्पादकता में कमी आई है और उस कारण से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें एडवाइज़री भी दी जाती है, उनको सलाह दी जाती है कि वहां पर कब बुवाई करनी चाहिए, लेकिन वहां जो नुकसान उनको हुआ है, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि क्या उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कोई नियोजन किया है, क्या कोई ऐसी योजना बनाई है, इस पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री राधा मोहन सिंह : इसके लिए हमारा सतत प्रयास चल रहा है और सतत योजनाएं चल रही हैं, जिनमें हम उनकी राजसहायता करते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, विदर्भ के अंदर बी.टी. कॉटन एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से वहां किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं और विशेष तौर पर जिस प्रकार का बीज कई बीज कंपनियां तैयार कर रही हैं, उनका नॉन-जर्मिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसी प्रकार से भारतीय किसान संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने...

श्री सभापति : आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्ज़ के बारे में अपनी कुछ आपत्तियां पेश की हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यह सवाल किसी व्यक्ति की आपत्ति का नहीं है। सवाल यह है कि इस संबंध में **...(व्यवधान)...**

SHRI DIGVIJAYA SINGH : This is about genetically modified seeds.

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री राधा मोहन सिंह : इस समय यह विषय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो निश्चित रूप से हम सबको निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री सभापति : थैंक यू, डा. विजयलक्ष्मी साधौ ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले : सर, मुझे भी सवाल पूछना है।

श्री सभापति : आप पहले सवाल पूछ चुके हैं, प्लीज़ Let somebody else get a chance.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, बी.टी. कॉटन के बारे में यहां चर्चा की जा रही है, जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि बी.टी. कॉटन के कारण विदभ और जहां से मैं आती हूं, मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र, वहां भी कॉटन लगाया जाता है। वैसे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बी.टी. कॉटन जमीन में ज्यादा पानी सोखता है और दिन-प्रतिदिन जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, तो क्या वैज्ञानिकों ने यह बात सरकार को बताई है? सर, ज्यादातर किसान बी.टी. कॉटन की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्ज भी ज्यादा लगते हैं और किसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि किसानों को वह अन्य वैराइटी की कपास बोने के लिए कहे? ...**(व्यवधान)**...

DR. K.P. RAMALINGAM : It is wrong, Sir.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, बी.टी. कपास की खेती अपने देश में बड़े पैमाने पर हो रही है और हमारा जो कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र है, उसने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का जो पूर्वानुमान लगाया था, उसमें प्रारंभ में कम वर्षा होने की संभावना थी, तो विदर्भ के किसानों को सलाह दी गई थी कि अब 16 जून से 20 जून तक गैर बी.टी. कपास की लगाएं, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो शुरू में बुवाई इस कारण से कम हुई और अब जब वर्षा ज्यादा हुई है, वहां मॉनसून अच्छा हुआ है, तो बीटी कॉटन की बुवाई शुरू हो गई है। ...**(व्यवधान)**...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर. बी.टी. कॉटन से जमीन की उर्वरक क्षमता क्या प्रतिदिन कम होती जा रही है? क्या वैज्ञानिकों ने ऐसा आपको कहा है? ...**(व्यवधान)**... सर, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है।

श्री राधा मोहन सिंह : मैंने यही बताया कि बी.टी. कॉटन के लिए ज्यादा moisture की जरूरत है, ज्यादा पानी की जरूरत है और बी.टी. कॉटन बोने की इजाजत देश में दे दी गई है। तो हमने, हमारी संस्था ने किसानों को सलाह दी कि वर्षा कम हो रही है, तो आप गैर-बी.टी. कॉटन लगाइए और जब मॉनसून अच्छा हो, तब बी.टी. कॉटन लगाइए, तो पूरे देश में यह चल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. That is enough.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मेरा जवाब नहीं आया है।

MR. CHAIRMAN: No, no; you cannot continue.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Chairman, Sir, the cotton production is having a lot of importance not only in Vidarbha but also, in its neighbouring State, Telangana. The trade and production is interdependent between Vidarbha and Telangana. In the usage of Bt cotton, as the hon. Minister has specified, there are a lot of complications, besides several advantages. We are yet to understand the real perception of the agricultural scientists, as far as the production is concerned. But farmers are showing some interest in growing the Bt. cotton. In such a situation, are we in a position to ensure the Indianized ideonised Bt. cotton seed availability within the country? This is what I would like to know from the Minister.

श्री राधा मोहन सिंह : जो बी.टी. बीज का जनरल सवाल है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसने एक टीम गठित की है। उस टीम में हमारे वैज्ञानिक भी हैं, उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। मुझे लगता है कि उस पर जल्दी निर्णय होने वाला है।

Loss of foodgrains

*446. SHRI SHADI LAL BATRA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the quantum and value of foodgrains lost due to pilferage, unsafe storage and damage during transit, during each of the last three years and the current year, so far, State-wise/Union Territory-wise, including Haryana;

(b) the total storage space available and foodgrains procured and stored during the same period, State and Union Territory–wise; and

(c) the effective steps taken/proposed to be taken by Government to prevent loss of foodgrains in the country?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAMVILAS PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Quantity and value of Central Pool foodgrains lost due to pilferage and in transit during last three years and current year, State–wise including Haryana is at Statement-I and II respectively (*See* below).Central pool foodgrains are stored safely after procurement till distribution. However, some quantity of foodgrains may get damaged / become non-issuable during storage due to various reasons such as storage pest attack, leakages in godowns, procurement of poor quality stocks, spillage during handling of